C M Y K

www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 97 नागपुर, शुक्रवार,3 मार्च 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

दु:खद है विश्वविद्यालयों के अंदर हिंसा और अशांति - प्रणब

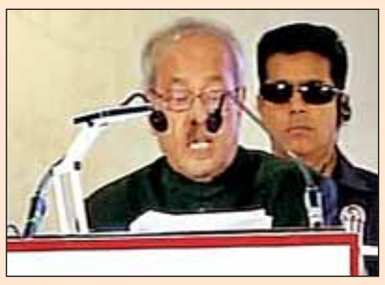

कोच्चि

पिछले कुछ महीनों से विश्वविद्यालयों के अंदर हो रही हिंसा पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गहरी चिंता जताते हुए उसे दु:खद बताया है। कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों का हिंसा और अशांति के मकड़जाल में फंसना दु:ख की बात है। अब समय आ गया है जब सामूहिक प्रयास से राष्ट्रभक्त और देश के हित को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है।

राष्ट्रपति मुखर्जी ने आगे कहा कि भारत में असहिष्णुता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारत प्रचीन समय से स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी वाला देश रहा है। उन्होंने कोच्चि में केएस राजमोनी मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए कहा कि तर्कसंगत आलोचना और असहमति का भी स्थान होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब हम महिलाओं के खिलाफ बर्बरता करते हैं तब हम अपनी अपनी सभ्यता को चोट पहुंचाते हैं। किसी भी समाज की जांच इसी बात से होती है कि वहां पर महिलाओं और बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार है।

अमेरिका ने पाकिस्तान में किया ड्रोन से हमला, 2 आतंकवादी मारे गए

पेशावर

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान में ड्रोन से हमला किया है। यह हमला अशांत पश्चिमोत्तर क्षेत्र कुर्रम एजेंसी में गुरुवार को किया गया। इसमें दो संदिग्ध आतंकी मारे गए। अमेरिका ने पाकिस्तान में पिछला ड्रोन हमला 21 मई, 2016 को किया था। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि सीआइए संचालित ड्रोन से अफगान सीमा के करीब कुर्रम के एक गांव में मिसाइल दागी गई। मौके पर ही दो संदिग्ध आतंकियों की मौत हो गई। इनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। हमले की जांच की जा रही है।

मणिपुर की जनसभा में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृहमंत्री

इंफाल

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गुरुवार को मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया।

गृहमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस द्वारा किया गया भ्रष्टाचार चरम पर है और यही सबसे बड़ी समस्या है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बोलते हुए गृहमंत्री ने कहा, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को अभ्यस्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और मणिपुर के मुख्यमंत्री भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 और 8 मार्च को दो चरणों में मणिपुर में विधानसभा चुनाव आयोजित किया जाएगा है। मतगणना के जरिए इसका परिणाम 11 मार्च को आएगा।

जाट आंदोलनकारियों ने 20 मार्च को दिल्ली जाम करने की दी चेतावनी

सरकार पर दबाव बनाने के लिए जंतर मंतर पर हुए जमा

नई दिल्ली

अपनी मांगों को लेकर जाटों ने गुरुवार को संसद मार्ग थाने के बाहर घेराव किया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक की मानें तो दोनों पक्षों की बातचीत के बाद फिलहाल धरना खत्म कर दिया गया है। अब 20 मार्च को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जाट नेताओं ने दिल्ली की दूध की सप्लाई बंद करने की भी चेतावनी दी है।

दरअसल, हरियाणा की खट्टर सरकार से नाराज जाट समुदाय के लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए गुरुवार को जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। पिछले साल हरियाणा में हिंसक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों की रिहाई, मुकदमा वापसी, आरक्षण लागू करने, मृतकों को मुआवजा और नौकरी देने समेत प्रदर्शनकारियों की सात मांगें हैं। जाट नेता यशपाल मलिक ने दावा किया है कि दिल्ली की सीमा पर स्थित चेकपोस्टों पर चेकिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों को आने से रोका जा रहा है। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर 50 हजार प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं।

जाट नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो होली के बाद 20 मार्च को दिल्ली में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि 20 मार्च को सभी जाट अपने ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य गाड़ियों से सुबह 8 बजे दिल्ली के आसपास हाइवे से कूच करेंगे। यहां वे दिल्ली आने जाने वाले रास्ते को भी रोकेंगे ताकि दिल्ली से बाहर जहां कोई रोकेगा, वहीं सड़क पर जाट बैठेंगे। फिर मामला चाहे 10 दिन चले या 10 साल पीछे नहीं हटेंगे। 20 मार्च के बाद हरियाणा के धरनों को महिलाएं संभालेंगी और पुरुष दिल्ली में रहेंगे। चारों तरफ हाइवे को जाम कर देने की भी चेतावनी जाट नेताओं ने दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के जाट भी आरक्षण के आंदोलन से जुड़ेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए जारी किया 894 करोड़ रुपयों का फंड

नई दिल्ली

महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों के लिए बीमा के तौर पर 893.83 करोड़ रुपयों का फंड जारी कर दिया है, जिनके अनाज को 2015-16 रबी के मौसम में बेमौसम बरसात और ओले पड़ने से क्षति पहुंची थी।

राज्य सरकार द्वारा जारी गए इस फंड को राज्य के विभिन्न हिस्सों में 26.88 लाख किसानों के बीच बांटा जाएगा। सर्वाधिक हर्जाना, 402 करोड़ रुपये को 13 लाख किसानों के बीच बांटा गया। औरंगाबाद और पुणे के किसानों को 340.57 करोड़ और 107.36 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मराठवाड़ा जिले में बारिश के कारण सोयाबीन व अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में करीब 34.26 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। 24.60 लाख हेक्टेयर की भूमि पर होने वाले फसलों के 2865.40 करोड़ रुपये की इंश्योरेंस कवर के लिए किसानों ने 56.91 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया। नवंबर 2015 से मार्च-अप्रैल 2016 के बीच फसलों के नुकसान के लिए 893.83 करोड़ की बीमा राशि दी गयी है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 2015-16 में सूखे के कारण कृषि उत्पादन काफी अधिक प्रभावित हुआ, लेकिन हर्जाना काफी अच्छा दिया गया है। पिछले एक साल में संतोषजनक इंश्योरेंस राशि मिलने के कारण प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना के लिए इस वर्ष हमें काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। फसल बीमा राशि में सोयाबीन, ज्वार, सूर्यमुखी, गेहूं, प्याज, धान आदि फसल हैं। राज्य द्वारा नियुक्त किए गए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से किसानों के खाते में बीमा राशि डाली जाएगी।

गैर सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफे पर बिफरी कांग्रेस

नई दिल्ली

गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर में बुधवार रात से प्रति सिलेंडर 86 रुपए की बढ़ोतरी के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इस सबसे बड़े इजाफे के साथ सरकार ने यह साफ जता दिया है कि उसकी आमलोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। बैंकों से पैसे की निकासी पर 150 रुपए तक प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज लगाने के निर्णय के लिए भी कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने बुधवार रात को चोरी छिपे अंदाज में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। पिछले छह महीने में इस तरह के सिलेंडर के दाम में 58 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने भी ट्विटर पर इसका आंकड़ा देते हुए कहा कि सितंबर 2016 में गैर सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 466 रुपए प्रति सिलेंडर थी जो बुधवार के इजाफे के बाद 737 रुपए का हो गया है। उनका कहना था कि गरीबों की बात करने वाली मोदी सरकार में आम आदमी की रसोई गैस की एक मद में महंगाई का यह आलम है।

सुरजेवाला ने निजी और सरकारी बैंकों के चार एटीएम ट्रांजेक्शन के बाद ग्राहकों से 150 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क लेने के फैसले के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया और कैशलेस के नाम पर आम आदमी की जेब पर वार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चार महीने बाद भी अभी बैंकों से निकासी पर पाबंदी नहीं हटाई गई है और इसी बीच अपने खाते से चार बार से अधिक पैसे निकालने पर 150 रुपए की फीस लगाकर आम आदमी को ही निशाना बनाया गया है। पार्टी ने आम आदमी की बैंकिंग जरूरत पर शुल्क लगाने का विरोध करने की भी घोषणा की।

कांग्रेस प्रवक्ता ने नोटबंदी के बाद तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों में कथित हेर-फेर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अर्थव्यवस्था की स्थिति नोटबंदी से ठीक नहीं है और उद्योग से लेकर रोजगार की दर नहीं बढ़ रही। ऐसे में जीडीपी के मानक कैसे बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि आंकड़ों के साथ भी खेल किया जा रहा है। सुरजेवाला ने इस नारियल जूस के बयान के सहारे पीएम मोदी के राहुल गांधी पर किए गए सियासी वार को भी झूठा ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल ने जो बयान कभी दिया ही नहीं उसका झूठा हवाला देकर देश के पीएम लोगों को भ्रमित करें तो इससे छोटी बात क्या हो सकती है।

भारत किसी भी हमले से निपटने को तैयार - पर्रिकर

नई दिल्ली

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोग किसी केमिकल वेपन्स के शिकार नजर आ रहे हैं।

डीआरडीओ के कार्यक्रम में बोलते हुए पार्रिकर ने कहा है कि अफगानिस्तान और उत्तरी हिस्सों से कई ऐसी रिपोर्ट आ रही है, मैंने तस्वीरों में देखा कि स्थानीय लोगों के शरीर पर चकते या किसी तरह के केमिकल वीपंस से प्रभावित थे। तस्वीरें विचलित करने वाली थीं। हालांकि, पर्रिकर ने यह भी कहा कि वह इस वक्त इस मुद्दे की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन देश को किसी भी किस्म की जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहें परमाणु, रासायनिक या जैविक हमलों का खतरा हो या न हो, लेकिन हम भविष्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

बता दें कि पिछले महीने पाकिस्तान के सिंध में शाहबाज कलंदर की दरगाह पर हुए फिदायीन हमले के बाद पाक सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। बौखलाया पाक सैकड़ों आतंकियों को ढेर कर चुका है। पाक ने कहा था कि हमले के पीछे अफगानिस्तान के जमात-उल-अहरार गुट का हाथ है।

राज्यों में भी मजबूत बनेगा मोदी सरकार का प्रचार तंत्र

नई दिल्ली

नोटबंदी पर सरकार के नजरिये को जनता के बीच सही तरीके से नहीं ले जा पाने की हकीकत से सतर्क मोदी सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। इसके मद्देनजर सरकार ने राज्यों में केन्द्र के सूचना व प्रचार तंत्र को मजबूत करने का सैद्धांतिक फैसला कर लिया है। इस रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार भारतीय सूचना सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी प्रमुख राज्यों की राजधानी में तैनात करेगी।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों में केन्द्र के प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने की इस कसरत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्री वैंकैया नायडू ने मंगलवार को इस सिलसिले में सूचना सेवा के वरिष्ठ अफसरों की एक बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में नायडू ने साफ कहा कि सरकार की व्यापक लोकहित से जुड़ी स्कीमों को जनता के बीच ले जाने

के लिए राज्यों में भी समन्वित प्रचार रणनीति की जरूरत है ताकि एक ओर लक्षित वर्ग तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा सके। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को चमका कर पेश किया जा सके।

सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बैठक में सरकार के प्रचार तंत्र प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो से जुड़े उन वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, जिनकी संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नति हो रही है। पीआइबी के अतिरिक्त महानिदेशक के रुप में करीब डेढ दर्जन अधिकारियों को संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नायडू ने इन अधिकारियों को राजधानी दिल्ली से बाहर राज्यों की राजधानी में तैनाती के लिए तैयार रहने का साफ संदेश दे दिया है। राज्यों के पीआईबी मुख्यालय में एडीजी स्तर के अधिकारी की तैनाती के जरिए सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करेगा।

महकमे के सूत्रों के अनुसार सरकार ने इन अफसरों को यह आश्वासन भी दिया है कि राज्यों में उनकी तैनाती के साथ वहां के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाएगा और कर्मचारियों की कमी को भी दूर करने का ख्याल रखा जाएगा। मोदी सरकार अगले तीन महीने में अपना तीसरा साल पूरा करेगी और अब सरकार के लिए अगले दो साल अपने कामकाज को चमकते अंदाज में पेश करने की चुनौती है। हालांकि प्रचार रणनीति के मामले में मोदी सरकार यूपीए के समय जनता और सरकार के बीच संवादहीनता को लेकर पहले से ही सचेत है मगर पहली बार खुद वैंकैया नायडू ने बीते दिनों स्वीकार किया कि नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार अपना नजरिया जनता के बीच सही तरीके से नहीं पहुंचा पायी।

यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली बनेगी सरकार - जेटली

वाराणसी

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बसपा के शासन को जनता ने अलग-अलग समय पर देखा और झेला है और जनता अब इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है और विद्रोह की मुद्रा में हैं।

जेटली ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा बसपा दोनों पार्टियों ने प्रदेश में एक ऐसा राजनितिक मॉडल लागू कर रखा था, जो समाज को जातीय आधार पर बांटने का काम कर रहा था। केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सपा का राज हो या बसपा का, कुछ विशेष वर्ग पर ही ध्यान दिया जाता है और बाकियों को अलग कर दिया जाता है। कुछ आपराधिक छवि के लोगों को मुख्य स्थान दे दिया जाता था।

वित्तमंत्री ने कहा कि सपा भले ही ऐसे लोगों से अलग होने की बात करें लेकिन बाद में ऐसे ही लोगों को टिकट दे देती है। बसपा ने आपराधिक लोगों को टिकट देकर कुछ वर्ग का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है।

इस तरह की राजनीति के खिलाफ अब लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है। सपा बसपा व कांग्रेस पार्टियां नोटबंदी का विरोध कर रही थीं ।

इनके विरोध को देखते हुए बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग भाजपा के साथ जुड़े है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इन तीन सालों में हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ी है, जबकि नोटबंदी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी।

उन्होंने कहा कि जब भी कही चुनाव आता है राष्ट्रवाद का मुददा उठ खडा होता है। जहां भी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठेगा वहां भाजपा खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि उत्तरप्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में घिरा पाक, भारत बोला-

आतंकरूपी 'दानव' अपने ही जन्मदाता को खा रहा है

नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवादी समूह तैयार करने का खामियाजा अब पाकिस्तान को खुद ही भुगतना पड़ रहा है और आतंकवाद का यह दानव अपने जन्मदाता को ही खा रहा है।

बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 34वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि अजित कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ आतंकी संगठनों को खड़ा किया था। अब यह उसी को तहस-नहस करने में लगा हुआ है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने मानवाधिकार के मामलों में पाकिस्तान के चौथे स्थान पर होने का भी मजाक उड़ाया। कुमार ने कहा, यह विडंबना है कि जो देश आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, मानवाधिकार के मामलों में वह चौथे नंबर पर है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देकर, हिंसा उकसाकर एवं उसका महिमामंडन करके हालात को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां के हालात देश का आंतरिक मामला हैं।

भारतीय राजदूत अजीत कुमार ने कहा कि भारत इसका उल्लेख करना चाहेगा कि पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला दिया जाना पूरी तरह से गुमराह करने वाला है क्योंकि पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर सूबे के हिस्सों को खाली करना जरूरी था क्योंकि इस पर उसका अवैध और जबरन कब्जा था। कुमार ने कहा कि ठोस और परिपक्व भारतीय लोकतंत्र ने एक बार साबित किया है कि किसी भी आंतरिक परेशानी का निवारण करने के लिए उसके पास मजबूत एवं उचित व्यवस्थाएं हैं।

2050 तक भारत में होंगे सबसे ज्यादा मुस्लिम!

नई दिल्ली

दुनियाभर में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और साल 2050 तक भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। यह बात अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने शोध में कही है।

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अगर इस्लाम इसी रफ्तार से बढ़ता रहा हो तो इक्कीसवीं सदी के अंत तक वो अनुयायियों की संख्या के मामले में इसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा। इस समय इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है।

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार साल 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी (करीब 30 करोड़) वाला देश बन जाएगा। अभी भारत इस मामले में इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है।

प्यू के अनुमान के मुताबिक, साल

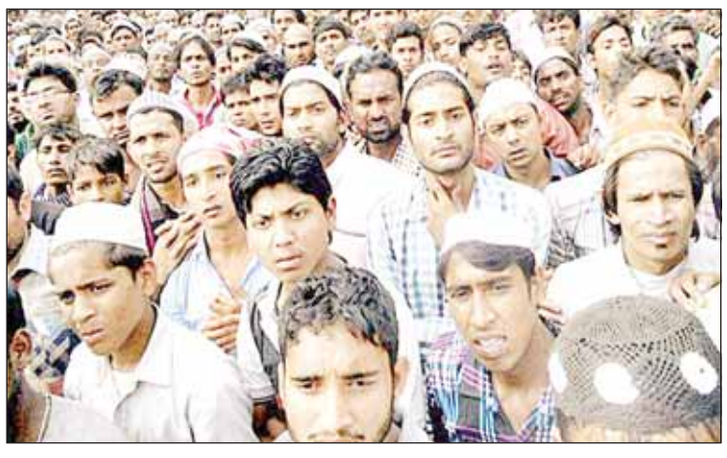

2010 के हिसाब से मुसलमानों की आबादी 1.6 बिलियन थी यानि पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या का 23 फीसदी। वर्तमान में, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। एक रिपोर्ट में प्यू ने कहा था कि आनेवाले दशकों में जहां पूरी दुनिया की आबादी में कुल 35 फीसदी का इजाफा होगा तो वहीं मुसलमानों की आबादी में करीब 73 फीसदी का इजाफा होगा और 2050 तक दुनिया में इनकी कुल जनसंख्या 2.8 बिलियन हो जाएगी।

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की आबादी बढ़ने के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर बाकी धर्मों से ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर मुस्लिम महिला के औसतन 3.1 बच्चे होते हैं जबकि बाकी धर्मों का ये औसत 2.3 है।

रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि, उनके माइग्रेशन और आईएस जैसे आतंकी संगठनों की हिंसक कार्रवाई ने कई देशों में इस धार्मिक समूह को डिबेट के बीच खड़ा कर दिया है।

हालांकि रिपोर्ट ने इस ओर भी इशारा किया है कि कई जगहों पर मुस्लिमों से जुड़े कई तथ्यों की जानकारी ही नहीं है। छोटी मुस्लिम आबादी के साथ रहने वाले अमेरिकियों ने भी माना है कि वे या तो इस्लाम के बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं।